under the jurisdiction of the State Government. That Government is fully aware of it and it is taking all possible steps.

Shri Mahanty: In regard to part (c) of the question, may I know if this grant has been rendered to the Government of Bihar pursuant to the recommendations of the Shivaraman Committee; if so, whether this Committee recommended similar grants for other areas like Eastern U.P. and Orissa which are also affected by drought?

Shri A. P. Jain: We do not discriminate between States and States.

Shri Mahanty: That is not the answer to my question. Sir, I crave your indulgence.

Mr. Speaker: The hon. Member wanted to know whether similar grants have been made to Eastern U.P. and Orissa.

Shri A. P. Jain: The States are constantly sending up proposals We examine those proposals and then decide on the same principles as are applicable to all the States. Some proposals have been received from the U.P. Government which are under examination. Some proposals have been received from Orissa, and either they may have been sanctioned or are under examination.

Shri Mahanty: Sir, this is a humanitarian question; it is not a political issue at all. We would like to know what particular bottle-neck is there in the State Governments of Eastern U.P. and Orissa receiving similar grants.

Mr. Speaker: This has been answered. The hon. Minister said that so far as U.P. is concerned the proposals are under examination, and so far as Orissa is concerned something has been done. Now, apart from that, I am sorry I allowed this question for the reason that the original question refers only to Bihar. Now, an hon. Member from Madras can get up and ask about Ramanathapuram, then a Member from Kerala and so on. We will go to the next question.

Shri Surendranath Dwivedy: Since the point has been raised, I think it is better that the position is clarified.

Mr. Speaker: The hon. Member can put down a question, and I will certainly allow to get the clarification.

Gliders Club

*463. **Shri P. G. Deb:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state what is the expansion programme for Gliders Club in the country.

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Humayun Kabir): Provision has been made for the opening of 10 new Gliding Centres in the Second Five Year Plan, but due to the foreign exchange difficulties it may not be possible to carry-out the programme in full.

Shri P. G. Deb: May I know when the Government is going to decide to start one in Orissa at Bhubaneshwar, in view of the fact that Bhubaneshwar has a Flying Club and there is also a unit of N.C C. Corps in Orissa?

Shri Humayun Kabir: We shall be very glad to receive such proposals either from the Orissa Government or from the Flying Club at Bhubaneshwar.

राष्ट्रीय राजपथ

*४६४. श्री राधेलाल व्यास : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की कौन-कौन सी राजधानियां राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित नहीं हैं;

(ख) क्या राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नागपुर योजना में संशोधन करने की कोई आवश्यकता समझी गई है; और

(ग) यदि हां, तो नये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राष्ट्रीय राजपथ से सम्बद्ध करने तथा उसे मध्य प्रदेश में और उसके बाहर अन्य राष्ट्रीय राजपथों से सम्बद्ध करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चंडीगढ़ और भोपाल ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें तमाम स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]

श्रीमन्, मझे क्षमा करेंगे कि इस विवरण में दो टाइपिंग एरर्ज हैं । "मुख्य" के स्थान पर "एक" और "में" की जगह "से" कर दिया जाय ।

श्री राघेलाल व्यास जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, उस में नागपुर योजना पर पुनर्विचार करने के तीन कारण बताये गये हैं—राज्यों का पुनर्गठन जैसे में होने वाला औद्योगीकरण और किसी प्रदेश का पिछड़ापन और उस में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा होना । मध्य प्रदेश राज्य में पुराने मध्य प्रदेश का २/३ भाग और तीन अलग राज्य भोपाल विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत मिले हैं, इसलिए राज्य-पुनर्गठन का सब से ज्यादा असर इस पर हुआ है । सब से ज्यादा हरिजन और आदिवासी इसी प्रदेश में हैं और सब से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र भी इसी में है । इस प्रदेश का औद्योगीकरण भी हो रहा है और हैवी इलैक्ट्रिकल मशीनरी प्लान्ट, कोयला और आयरन ओर का काम हो रहा है । इन सब बातों को देखते हुए क्या मध्य प्रदेश को तृतीय पंच-वर्षीय योजना तक अटकाये रखना सही है और इस बात पर विचार करो नहीं किया जा रहा है कि इस को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ही रख दिया जाय ?

Mr. Speaker: The hon Member comes occasionally; therefore, he has put all the questions together

श्री राज बहादुर : जो सूचना और तर्क माननीय सदस्य ने दिये हैं, वे सब विचारणीय हैं । मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि उन को शायद यह भी ज्ञात है कि भोपाल को राजधानी बने हुए केवल बारह चौदह महीने या इससे कुछ अधिक समय हुआ है ।

श्री राघेलाल व्यास : चंडीगढ़ तो राजपथ से थोड़ी ही दूर है लेकिन भोपाल का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी कोई सम्बन्ध नहीं है । मैंने पिछले बजट अधिवेशन में कुछ सुझाव दिये थे और माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे उन पर विचार करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है, यदि हां तो क्या ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराऊं कि माननीय शास्त्री जी ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अवश्य ही हमारे राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई बढ़ाई जानी चाहिये । किन्तु यह निर्भर इस बात पर है कि कितनी धनराशि हमें इस काम के लिए मिल सकती है ।

श्री राघेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी किया जा सकेगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना तक मध्य प्रदेश सरकार का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था और एक अब पूछा है । उसमें उन्होंने खुद ही अपनी बात को काट दिया था । एक बार तो कहा है कि इतना पिछड़ा हुआ वह प्रदेश है और दूसरी बार कहा कि वही ज्यादा से ज्यादा उद्योगीकरण हो रहा है । इन दोनों का मेल ठीक नहीं बैठ रहा है । मगर उसको इतना पिछड़ा कहना ठीक नहीं है । भोपाल काफी अच्छा और बढ़ता हुआ शहर है । जहां तक सड़कों की बात है अभी हमारे साथी ने बताया है कि हमारे नैशनल हाइवेज का जो १३,८०० का फासला है उसको बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमिशन ने

अभी मंजूरी नहीं दी है । मगर मेरा विचार है कि कम से कम उसको १५००० तक करना चाहिए । मैंने इसी बात को खास तौर पर खयाल में रखकर यह प्रस्ताव रखा था जिससे ऐसे प्रदेश जो नये बने हैं उनकी राजधानियों को सड़कों से मिलाने का इंतिजाम किया जा सके । उसमें हम मध्य प्रदेश का ध्यान अवश्य रखेंगे ।

श्री त्यागी : यह नेशनल हाइवेज बनाने की स्कीम बड़े बड़े शहरों को मिलाने तक ही महदूद है या उन पहाड़ी इलाकों में भी सड़कें बनाई जायेंगी जहां कोई रास्ते नहीं हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहाड़ी इलाकों की सड़कें बनाने की जिम्मेदारी माननीय सदस्य जिस प्रदेश में रहते हैं, उनकी है । लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम ने काफी रुपया पहाड़ी सड़कें बनाने के लिए प्रदेशों की सरकार को सहायतार्थ दिया है ।

Shri Heda: The hon. Minister has already replied to a certain extent, but I would like to know clearly from him what the target of mileage for the national highways in the Nagpur plan was, and what is the number already accepted by the Planning Commission for the five-year period, and what is the further mileage for which the Ministry is pressing now?

Mr. Speaker: He said 13,000 to 15,000.

Shri Raj Bahadur: So far as I know, the question of national highways in relation to the Nagpur plan does not arise, because the Nagpur plan, so far as I know first considered the construction of pucca roads and gravel roads, that is, rural or unmetalled roads and pucca or metalled roads The total mileage that was set by them was 3,31,000 So far as the national highways are concerned, they were first declared roundabout 1950 or later and the mileage accepted for the national highways was 13,800

श्री मा० सा० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने त्यागी जी को पहाड़ी प्रदेशों में सड़कें बनाने के बारे में दिया है क्या उसी तरह का आश्वासन राजस्थान के पहाड़ी प्रदेश वालों को भी मिल सकेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बात यह है कि माननीय त्यागी जी बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं और आप बहुत नीचे पहाड़ों पर । इसलिए उनको यह आश्वासन दिया गया है ।

Raja Mahendra Pratap: What about bridges on these roads? I know in certain places there are only boat bridges and it is very difficult to go through these boat bridges, Is there any plan for placing pucca bridges on these highways?

Shri Raj Bahadur We have got a definite plan for the construction of road bridges also, and they are covered by the general Plan But it is a fact that certain rivers will remain unbridged even at the end of the Second Plan

Interim Relief for Extra Departmental Agents of Postal Deptt.

+

*465. { **Shri N R Munisamy:**
Shrimati Ila Palchoudhuri:

Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that extra departmental agents of the Postal Department were given an interim relief of Rs 2 per month,

(b) if so, whether it was in pursuance of any Committee's recommendations, and

(c) the amount involved in this grant of interim relief?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): (a) Yes

(b) No.

(c) Rs. 2,04,000 per month.